

न मुक्ताभिनं माणिक्यैः न वस्त्रैर्न परिच्छदैः।  
अलङ्कियेत शीलं केवलेन हि मानवः॥  
मौती, माणक, वस्त्र या पहनावे से नहीं, पर केवल  
शील से ही इंसान विभूषित होता है।

अमर उजाला

लखनऊ



सुप्रभात

चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी, विक्रम संवत् 2076

mycity

रविवार • 14.04.2019



08

भए प्रगत  
कृपाला  
दीनदयाला...  
से गूजे मंदिर

mycity

रविवार • 14.04.2019

महिला • संस्कृति • समाज

अमर उजाला

Lucknow.amarujala.com

page  
7

# घोषणापत्र में शामिल हों जनता के मुद्दे तो बढ़े मतदान प्रतिशत

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत का कम होना लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। शहरी और पड़े-लिखे मतदाता ही मतदान करने में पिछड़े साबित हो रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है जो लोगों को लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने से रोक रही है, इसके कारण और समाधान तलाशने की मंशा से शनिवार को 'अमर उजाला' कार्यालय में फोकस ग्रुप की शुरुआत हुई। फोकस ग्रुप के आगाज पर शहर के नामचीन और बुद्धिजीवी वर्ग को आमंत्रित किया गया। अपराजिता 100 मिलियन स्माइल्स

मुहिम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में शहर की इन खास शख्सियतों ने इस अहम मुद्दे पर अपनी बात रखी और समाधान सुझाए, पेश है उस पर एक रिपोर्ट-

लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के मुद्दे पर फोकस ग्रुप का आयोजन, बुद्धिजीवियों ने रखी अपनी राय



चर्चा के दौरान निकल कर आई ये खास बातें

- मतदाता सूची की गड़बड़ियों की वजह से भी काफी लोग वोट नहीं डाल पाते हैं। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
- जनता को राजनीतिक दलों का चुनावी घोषणापत्र तय करने का हक मिलना चाहिए।
- चुनाव आयोग को मतदान प्रतिशत सुधारने के लिए कड़े निर्देश भी देने चाहिए। जिससे कि इसमें लगे लोग लापरवाही न कर सकें।
- मतदान करने वालों को पुरस्कार और न करने वालों के लिए कुछ सजा का निर्धारण होना चाहिए।
- मतदान स्थल पर लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ानी चाहिए।
- बच्चों के माध्यम से जागरूकता फैलाने का प्रयास और बड़े स्तर पर करना चाहिए।
- लोकतंत्र की शिक्षा दी जाए और यह बताएं कि वोट देना कितना जरूरी है। इसके लिए पाठ्यक्रम में व्यवस्था की जानी चाहिए।
- मतदान से पहले और बाद में हर प्रत्याशी का किसी निर्धारित अवधि तक क्षेत्र में रहना अनिवार्य किया जाए। इससे पैराशूट प्रत्याशी पर रोक लगेगी।
- चुनाव के मुद्दों पर लगातार चर्चा करने की जरूरत।
- प्रत्याशियों की योग्यता भी तय करने की जरूर है।

संस्थाओं की मजबूती के साथ बेहतर होगा जनतंत्र



चुनाव जनतंत्र का महापर्व है। इसी से हमारी सरकार तय होती है। संसकारी जनतंत्र होने पर सरकार भी संसकारी होगी। इसमें संस्थाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जितनी मजबूत ये संस्थाएं होंगी, देश में जनतंत्र भी उतना ही मजबूत होगा। संस्थाओं को चाहिए कि वे मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सहयोग करें। संस्थाओं के सहयोग से जब वोट प्रतिशत बढ़ेगा तो देश में मजबूत और संसकारी सरकार का गठन होगा।

-प्रो. सुरेंद्र प्रताप सिंह, कुलपति, लविवि

चुनाव के मुद्दों पर स्वस्थ चर्चा की जरूरत



लोकतंत्र की यह विडंबना है कि बहुत से लोग मुद्दों से परिचित ही नहीं होते। इस वजह से भेंड़चाल की तरह मतदान होता है। इसे रोकने के लिए जरूरी है कि हम अपने आसपास इस पर स्वस्थ चर्चा करें। स्वस्थ चर्चा से ही असल मुद्दे सामने आएंगे। इसके अलावा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपने घर से दूर रहने वाले लोगों को भी मतदान का मौका देने की

व्यवस्था होनी चाहिए।

-डॉ. सीएम नौटियाल, पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक

घर-परिवार से शुरुआत की जरूरत

लोकतंत्र के इस पर्व में तंत्र हावी हो रहा है और लोक कहीं गुम होता जा रहा है। लोकतंत्र को पहले अपने घर और



परिवार से जोड़ें। आजकल का युवा सोशल मीडिया से सीख रहा है। लेकिन अफसोस है कि उसे वास्तविक लोकतंत्र की शिक्षा नहीं दी जा रही। सामाजिक विसंगति पैदा हो गई है। प्रबुद्धजन इस महापर्व में कम ही प्रतिभाग कर रहा है। साथ ही यह भी व्यवस्था हो कि जो जहाँ हो वहाँ पर वोट कर सके।

-कृष्ण कुमार यादव, निदेशक, डाक विभाग

मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाने की हो कोशिश



समाज में दो तरह के नागरिक हैं। पहले जो जागरूक हैं और दूसरे जो जागरूक नहीं हैं। देखा जाता है कि जो सामान्य तौर पर जागरूक नहीं हैं, लेकिन वोट देने के मामले में वे आगे रहते हैं। यह बात और है कि उन्हें यह भी पता नहीं होता कि क्यों और कैसे वोट करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले समाज में चल रहे मुद्दों से उन्हें परिचित कराने की जरूरत है।

-मदुला गर्ग, वरिष्ठ रंगकर्मी

अकर्मण्यता के मुद्दे हो रहे हावी



अकर्मण्यता के मुद्दे हावी हो रहे हैं। साथ ही निशुल्क सेवाएं और आर्थिक सहायता पहुंचाने जैसे मामलों से लुभाया जा रहा है इससे भटकाव हो रहा है। युवाओं को अच्छी शिक्षा और रोजगार की जरूरत है। ऐसे मुद्दों पर ज्यादा काम होने चाहिए। सरकार को चाहिए कि वे संविधान के मुद्दों को लेकर

जनता से जुड़ें।

- डॉ. भरत राज सिंह, पर्यावरणविद